सूचना एवं जन–सम्पर्क विभाग, बिहार
प्रेस–विज्ञप्ति

संख्या– 371
16/04/2026

सीमावर्ती गांवों के समग्र विकास को गति देगा वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम–II: डॉ. एन. विजयलक्ष्मी

पटना में आयोजित कार्यशाला में प्रभावी क्रियान्वयन, डेटा आधारित मॉनिटरिंग एवं विभागीय समन्वय पर दिया गया विशेष जोर”

पटना दिनांक 16.04.2026:– योजना एवं विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा आज “वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम–II (VVP-II) के कार्यान्वयन” विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय के सम्मेलन कक्ष, में किया गया। कार्यशाला का उद्देश्य कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन, विभागीय समन्वय तथा मॉनिटरिंग तंत्र को सुदृढ़ बनाना

कार्यक्रम की अध्यक्षता अपर मुख्य सचिव, योजना एवं विकास विभाग, डॉ. एन. विजयलक्ष्मी ने की। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम–II सीमावर्ती क्षेत्रों के समग्र एवं सतत विकास के लिए एक महत्वपूर्ण पहल है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित किया कि योजना के क्रियान्वयन में समन्वित प्रयास, डेटा-आधारित मॉनिटरिंग तथा फील्ड स्तर पर प्रभावी निगरानी सुनिश्चित की जाए, ताकि निर्धारित लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति हो सके।

इस अवसर पर विशेष सचिव, गृह विभाग, श्रीमती के. एस. अनुपम ने कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने सुरक्षा एवं विकास के बीच संतुलन स्थापित करने पर बल दिया।

श्री मुकेश कुमार, डीआईजी, सशस्त्र सीमा बल (SSB) ने अपने संबोधन में कहा कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकासात्मक गतिविधियां स्थानीय समुदाय के विश्वास एवं सहभागिता को सुदृढ़ करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय के निदेशक (VVP) श्री मनीष श्रीवास्तव ने कार्यक्रम के राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम–II के माध्यम से सीमावर्ती गांवों को बुनियादी सुविधाओं, आजीविका एवं कनेक्टिविटी के क्षेत्र में सशक्त बनाया जा रहा है, जिसमें राज्यों की सक्रिय भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) के वरिष्ठ तकनीकी निदेशक श्री दीपक कुमार ने कार्यक्रम के तकनीकी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए डेटा प्रबंधन, डिजिटल मॉनिटरिंग एवं आईटी आधारित समाधानों की भूमिका को रेखांकित किया।

कार्यशाला में सीमावर्ती जिलों—पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज, कटिहार, पूर्णिया, सहरसा आदि के जिला पदाधिकारी एवं संबंधित विभागों के अन्य अधिकारियों ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लिया तथा इन सीमावर्ती जिलों के जिला योजना पदाधिकारी एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी सम्मिलित हुए। इसके अतिरिक्त योजना एवं विकास विभाग के प्रधान सचिव श्री मयंक वरवड़े, मूल्यांकन निदेशालय के निदेशक श्री रविश किशोर, विभाग में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम–II की सहायक नोडल पदाधिकारी श्री सुजाता कुमारी एवं अन्य संबंधित हितधारकों की सक्रिय भागीदारी रही।

कार्यशाला के दौरान विभिन्न तकनीकी सत्रों का आयोजन किया गया, जिनमें कार्यक्रम के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन से संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई। प्रतिभागियों ने सक्रिय भागीदारी करते हुए अपने अनुभव एवं सुझाव साझा किए।